देने के लिए निम्नोक्त कुछ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) 50 प्रतिशत लागत पर शहतूती कलमों/पौधों की सप्लाई ।

(2) सीमान्त कृषकों को कीटपालन उपस्करों की निशुल्क सप्लाई ।

(3) यूजी फलाई नियन्त्रण के लिए 50 प्रतिशत लागत पर नायलोन जालों की सप्लाई ।

(4) द्विफसलीय रेशम कीटपालकों और रीलरों को प्रोत्साहन बोनस ।

(5) किसानों के अध्ययन दौरे की व्यवस्था करना ।

(6) रीलिंग में प्रशिक्षण ।

(7) मल्टी एण्ड रीलिंग यूनिटों की स्थापना के लिए रीलरों को सहायता देना ।

अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग के लिए विशेष निधियां

3602. **श्रीमती कैलाशपति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग के लिए विशेष निधियां आबंटित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो नई प्रणाली को कब तक और किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा ;

(ग) क्या विद्युतकरघा / हथकरघा उद्योग के विकास के लिए विशेष निधियां आबंटित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की कई प्लान और नॉन प्लान योजनाएं हैं । ऐसी योजनाओं इस क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाता है और नई योजनाएं अनुमोदित की जाती हैं । तदनुसार नई योजनाओं के लिए धनराशि आबटित की जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) चालू "प्लान और नॉनप्लान" योजनाओं के लिए वर्ष 1992–93 के लिए बजट प्राकलन में निम्नलिखित राशि आबटित की गई है :—

(लाख रुपयों में)

हथकरघा	पावरलूम
25538.40	318

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

3603. **श्री अजीत जोग :**

श्रीमती कैलाशपति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1992 में अब तक किन-किन देशों को हथकरघा वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या विदेश में भारतीय हथकरघा वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारतीय हथकरघा माल का विश्व में सौ से अधिक देशों को निर्यात किया जा रहा है । वर्ष 1989–90, 1990–91 और 1991–92 के दौरान प्रमुख बाजारों को सूती हथकरघा फाब्रिक और प्रमुख बाजारों को सूती हथकरघा फैब्रिक और मेड-अप्स के निर्यात के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । (**देखिये** परिशिष्ट 164 अनुपल सं० 58)

(ख) और (ग) सरकार ने हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, विदेश व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित

करना, शुल्क वापसी की मंजूरी देना और उचित कोटा नीति-परक उपाय करना।

विकास आयुक्त हथकरघा आधुनिकीकरण/नवीकरण/हथकरघों द्वारा उत्पादित फब्रिकों की उत्पादकता और क्वालिटी में सुधार करने के लिये करघों के क्रय के लिये सहायता उपलब्ध कराने के लिये एक योजना का परिचालन कर रहा है। देश भर में फैले 23 बुनकर सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र और 3 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संथान नई डिजाइनों का विकास, बुनाई और प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी में सुधार, हथकरघा संबंधी कुशलता में प्रशिक्षण आदि में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास ने बुनकर सेवा केन्द्र, हथकरघा निदेशालय और अन्य संबद्ध संगठनों के सहयोग से मुख्य रूप से निर्यात के लिये हथकरघा उत्पादन सुविधाओं के उन्नयन के लिये कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के एक उद्देश्य हैं: इन केन्द्रों में मौजूदा नियोजित प्रौद्योगिकी और प्रोसेस को अभिज्ञात करना, उत्पादकता में वृद्धि करने और उत्पादन की क्वालिटी में सुधार करने के लिये उपयुक्त उपाय करना।

U.N.D.P. Assistance for revival of Jute Industry

3604. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to Unstarred Question No. 1866 given in the Rajya Sabha on 27th July, 1992 and state:

(a) the manner in which Government propose to diversify the distribution of 23 million US $ loan of U.N.D.P. for its proper utilisation; and

(b) whether Government also propose to import advanced technology for better and optimum utilisation of jute fibre?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) UNDP assistance of US $ 23 million along with counterpart funds provided by the Government of India for the implementation of the National Programme for the development of the jute sector would be distributed amongst various implementing agencies for development of jute agriculture, development of new products, employment generation, development of jute machinery sector, R&D institution building, private sector development, export promotion, human resource development, introduction of effective systems of coordination etc., according to the proposals/schemes sanctioned by the Standing/Steering Committees set up for this purpose. Advanced technology for better and optimum utilisation of jute would also be imported, if required.

Manufacture of Janata Dhoties and Sarees

3605. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that apart from word famous Chanderi Sarees Madhya Pradesh is also an important centre for the manufacture of cotton janata dhoties and sarees;

(b) if so, what is the approximate annual production of cotton janata dhoties and sarees in the State and their actual production during the last three years; and

(c) what incentives Government proposes to give to the manufacturers of janata dhoties and sarees in Madhya Pradesh to give a boost to the production?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) The janata cloth produced in Madhya Pradesh has been 15.85 million square metres, 16.42 million square metres and 17.63 million square metres during 1989-90, 1990-91 and 1991-92 respectively.